14 लाख की वसूली के बाद भी जच्चा बच्चा को नहीं बचाया एशियन अस्पताल ने

फरीदाबाद, (म.मो.)। लूट खसौट और मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने में शहर का एशियन अस्पताल भी दिल्ली के मैक्स अस्पताल से किसी तरह पीछे नहीं है। वैसे इस अस्पताल के कारनामे किसी से छुपे भी नहीं हैं। हाल में इस अस्पताल की लापरवाही से एक विवाहिता और उसके गर्भ में पल रहे करीब सात महीने के बच्चो को तो अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही अस्पताल ने परिजनों से करीब 14 लाख रुपये भी वसूल लिए।

नचौली गांव निवासी दुष्यंत नागर ने बताया कि उनके बड़े भाई सीताराम की 20 वर्षीया बेटी स्वेता उर्फ सीमा का विवाह पलवल के गांव कुशक बड़ौली में रहने वाले शिव के साथ हुआ था। करीब छह सात महीने के गर्भावस्था में सीमा पिछले दिनों अपने मायके में आ गई थी। गत 1× दिसंबर को बुखार होने के कारण सीताराम ने गलती से सीमा को एशियन अस्पताल में दाखिल करवा दिया था जहां डाक्टर जच्चा व बच्चा की जान बचाने का दावा करते हुए इलाज करने लगे।

इसके बाद कभी इलाज तो कभी इंजेक्शन मंगवाने के नाम पर अस्पताल द्वारा वसूली का खेल शुरू हो गया। दुष्यंत नागर का दावा है कि अस्पताल करीब 100 इंजेक्शन लगाने का बिल उन्हें हर रोज थमा देता था। दो दिन बाद डाक्टरों ने बताया कि जच्चा बच्चा की जान बचाने के लिए सीमा का ऑपरेशन करना जरूरी है और वे साढ़े तीन लाख रुपये तुरंत जमा करवाने के लिए कहने लगे।

सीताराम ने किसी तरह दो लाख रुपये जमा करवाए। लेकिन वे पूरी रकम लिए बिना ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में उन्होंने किसी तरह डेढ़ लाख और जमा करवा दिए। रुपये जमा करवाने के करीब 48 घंटे बाद 17 दिसंबर को डाक्टरों ने ऑपरेशन कर मृत बच्चो को निकाल दिया। लेकिन तब तक इनफेक्शन फैल जाने के कारण सीमा की तबीयत और बिगड़ गई। ऑपरेशन के बाद डाक्टरों ने आंत फटने की बात कह कर सीमा को बेंटीलेटर पर रख दिया। 26 दिसंबर तक वैंटीलेटर पर रखकर अस्पताल हर रोज करीब एक लाख रुपये वसूलने लगा।

दो दिन आईसीयू में रखने के बाद दोबारा तबीयत बिगड़ने की बात कह कर डाक्टरों ने सीमा को दोबारा वैंटीलेटर पर डाल दिया। इस दौरान हर रोज बिल जमा करवाने का दबाव भी बनाया जाता रहा। पांच जनवरी को रात करीब साढ़े नौ बजे डाक्टरों ने बताया कि सीमा की मौत हो चुकी है। छह जनवरी को बकाया बिल वसूलने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा गया। उन्होंने काफी विरोध जताया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एक नहीं सुनी।

एशियन अस्पताल और शहर के अन्य निजी अस्पतालों की लापरवाही और लूट खसौट के मामले आए दिन उजागर होते रहते हैं। लेकिन सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गूजर व अन्य विधायकों और मंत्रियों को आम जनता की परेशानी और अस्पतालों की लूट खसौट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जरूरत पड़ने पर यही निजी अस्पताल उनकी सेवा करने के लिए हमेश तैयार खड़े रहते है। संदर्भवश सुधी पाठकों को याद करा दें कि एशियन अस्पताल के मालिक डॉ. एनके पांडे को लूट खसौट एवं जनविरोधी जघन्य कारनामों के बावजूद भारत सरकार ने पदमश्री पुरस्कार से भी स मानित किया था। गौरतलब है कि मजदूर मोर्चा ने एशियन अस्पताल के मालिक डॉ एनके पांडे के बारे में गत 1 से 15 मार्च 2015 के अंक में हर अस्पताल चोर, डॉ. पांडे का सिरमौर इलाज का नाम, लूटमार का, पदमश्री का इनाम का इनाम की हैडिंग से खबर छप कर पाठकों को पहले ही अगाह कर चुका है। इससे समझा जा सकता है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, इलाज के नाम पर जनता इन चिकित्सा व्यापारियों द्वारा यूंही लूटती पिटती व मरती रहेगी।

8 1-15 मार्च 2015 मजदूर मोर्चा पाक्षिक

हर अस्पताल चोर, डॉ. पांडे का एसियन सिरमौर

इलाज का नाम, लूटमार का काम, पद्मश्री का इनाम

टेस्टों में डाक्टरों की कमीशनखोरी

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की दाढी उतनी ही सफ़ेद है। गुड़गांव के फ़ोर्टिस अस्पताल की लूट उतनी ही शातिर है। राष्ट्रीय मीडिया में छाया रहा इस अस्पताल का 18 लाख में मरीज़ मारने का 'कारनामा' भुला दिया गया है। यह भी भुला दिया गया है कि इन्क्वायरी कराने व मुकदमे दर्ज होने के ढोंग का सिलसिला कितना लचर साबित हुआ है।

सिलसिले को समझने के लिये 'मज़दूर मोर्चा' के 1-15 मार्च 2015 के अंक में प्रकाशित फ़रीदाबाद के एशियन अस्पताल की लूट-मार का ब्योरा विस्तार से ऊपर दिये गये छायाचित्र में देखा जा सकता है। सरकार के सहयोग एवं संरक्षण में चलने वाला यह काला धंधा आज भी एशियन जैसे तमाम अस्पतालों में चल रहा है। इन अस्पतालों का सीधा समीकरण है-जनता को काटो, नेताओं व अफ़सरों को पालो, ये अपने विज्ञापनबाज़ी व मार्केटिंग पर अंधाधुंध खर्च करते हैं। जबकि स्टाफ़ को पूरा वेतन भी नसीब नहीं होता। यहां दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के दाम बेशक तय नहीं पर येन-केन प्रकारेन लाखों का बिल बन जाना तय होता है।

एक सभ्य समाज में एशियन अस्पताल के मालिक डॉ. एनके पांडे जैसों को सारी उम्र जेल में होना चाहिये था। आज के भारतीय समाज में वह पद्म श्री लेकर अपनी दुकानदारी को और चमका रहा है।

केन्द्रीय श्रम मन्त्री से हरियाणा श्रम मंत्री ने 'क्वालिटी' की 'गुहार' लगाई

नई दिल्ली (म.मो.) दिनांक 2 जनवरी को हरियाणा के श्रम मंत्री नायब सिंह सैनी केन्द्रीय श्रम मंत्री से एक मीटिंग करने पहुंचे थे। साथ में लाये थे राज्य के ईएसआई हैल्थ केयर के डायरेक्टर मलिक को। उधर केन्द्रीय श्रम मंत्री ने डी जी, ईएसआईसी दीपक कुमार, मेडिकल कमिश्नर कटारिया व 2-4 अन्य अधिकारियों को भी बुला लिया था।

अपने अधिकारों से अन्जान, काम-काज में ज़ीरो नायब सिंह सैनी केन्द्रीय मन्त्री से यह गुहार लगाने आये थे कि वे हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों की क्षमता एवं कार्यकुशलता को बढायें। ईएसआई व्यवस्था का थोड़ा-बहुत ज्ञान रखने वाला हर व्यक्ति यह जानता है कि राज्य सरकार अपने राज्य की ईएसआई व्यवस्था में क्या कुछ कर सकती है। लेकिन लगता है कि श्रम मंत्री सैनी को तो कोई ज्ञान है नहीं और डॉ. मलिक कोई काम करके राज़ी नहीं।

'मज़दूर मोर्चा' बरसों से लिखता आ रहा है कि राज्य के तमाम अस्पतालों व डिस्पेंसरियों के लिये तमाम तरह-चपरासी से लेकर डॉक्टरों तक-की भर्ती राज्य सरकार कर सकती है। इसी तरह तमाम उपकरणों व साज़ो-सामान व दवाओं आदि की खरीद का काम भी राज्य सरकार को ही करना होता है। इसमें केन्द्र सरकार या ईएसआई कार्पोरेशन का कोई दखल नहीं होता। हां उनकी ओर से कुछ नियम व कायदे जरूर बनाये गये हैं ताकि राज्य सरकार पेसे की बर्बादी न कर सके।

अपने इस दायित्व पर होने वाले खर्चे के लिये राज्य सरकार का ईएसआई हैल्थ केयर विभाग बजट बनाता है। इस बजट का केवल 12 प्रतिशत राज्य सरकार देती है जबकि व शेष 88 प्रतिशत ईएसआई कार्पोरेशन को देना होता है।

अब राज्य सरकार यदि बजट ही 125-150 करोड़ का बनाये तो इसमें ईएसआईसी क्या कर सकती है? हरियाणा सरकार को वास्तविक जरूरत के अनुसार 800 (या 900 या 1000) करोड़ का बजट बनाने से किसने रोका है? 800 करोड़ के बजट में से राज्य को तो केवल 100 करोड़ ही खर्च करना पड़ेगा शेष 700 करोड़ तो ईएसआईसी को देना है।

आवश्यकतानुसार बजट को बढाकर आवश्यक स्टाफ़ को भर्ती किया जा सकता है। इससे एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरे राज्य के मज़दूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा। हरियाणा सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेक्टर 8 के अस्पताल में मात्र 17 डॉक्टर हैं जबकि 50 बेड पर कम से कम 40 होने चाहिये और 200 बेड पर 70 होने चाहियें। एक डॉक्टर पर 5 अन्य स्टाफ़ के हिसाब से 1000 लोग अलग से होने चाहिये। अब यह काम केन्द्र सरकार को तो करना नहीं, यह काम तो राज्य सरकार का है जो वह कर नहीं पा रही।

लेकिन जनाब नायब सिंह सैनी, माननीय श्रम मंत्री हरियाणा सरकार, न जाने कौन सा तेल बेचने केन्द्रीय श्रम मंत्री के पास गये थे।

सुषमा स्वराज : कहा गई वो बसंती??जो एफडीआई के विरोध में पूरी रात नाची थी?? ड ड ड ड डान्स बसंती?? एफ़डीआई के हाट में !

उत्तर प्रदेश रंग दिया भगवा, योगी की कानून व्यवस्था अगवा

मजदूर मोर्चा ब्यूरो, लखन

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा की मेहरबानी से पदासीन हुए थे। अब उन्हें भगवा रंग में ही अपनी राजनीतिक सुरक्षा दिखाई पड़ रही है।

योगी के पास न कोई शासन-प्रशासन का अनुभव है और न सामाजिक-आर्थिक चिन्तन की क्षमता। लिहाज़ा उनकी तमाम घोषणायें ओर पहलबाजियां खोखली सिद्ध हो रही हैं। सबसे बुरा हाल कानून-व्यवस्था का इसलिये भी नज़र आता है क्योंकि योगी ओर उनकी पार्टी बढ-चढ कर पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की बिकी हुई कानून-व्यवस्था को कोसा करते थे।

सरकार की निष्क्रियता का अनुमान इस बात से ही लग जाता है कि राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों में जो गर्म वर्दी नवम्बर तक बच्चों को मिल जानी चाहिये थी, उसकी प्रक्रिया ही रद्द करनी पड़ी। करण? जिस गति से लाल फ़ीताशाही इस प्रक्रिया को चला रही थी, शायद मई-जून तक ही वर्दियां मिल पातीं।

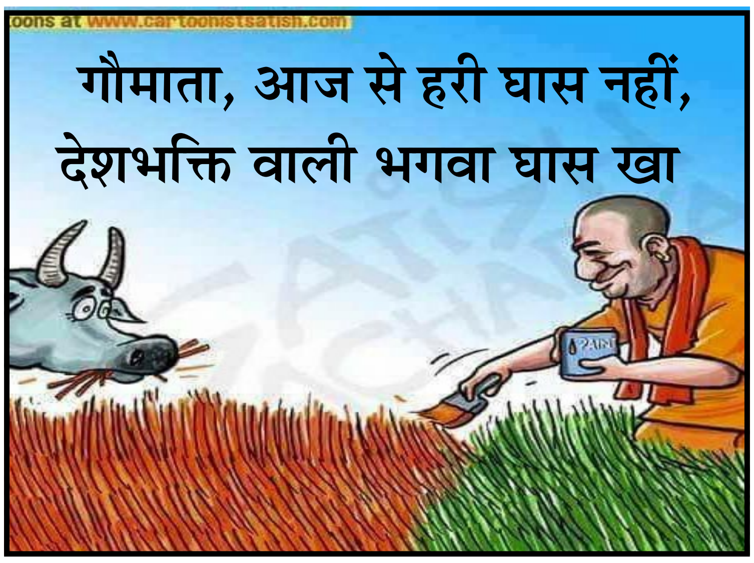

oons at www.cartoonistsatish.com
गौमाता, आज से हरी घास नहीं, देशभक्ति वाली भगवा घास खा
PAINT

जिस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में सैंकड़ों बच्चों की मौत पर राष्ट्रीय स्तर का हंगामा महीनों चलता रहा, वहां के रिकार्ड रूम में आग लगी दिखा कर सभी सम्बन्धित फ़ाइलों को जल जाने दिया गया। दोषी कौन? न पता है न कभी पता चलेगा। हां, सैफ़ई की तर्ज पर गोरखपुर महोत्सव जरूर मनने लगा है।

अवैध खनन रोकने के नाम पर पूरे प्रदेश में रेत निकालने पर बंदिश लगा दी गयी है। जहां आम उपभोक्ता को काले बाज़ार में इस रेत के तिगुणे-चौगुणे दाम चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं संघी ब्रांड के नेताओं को खुल कर लूटने-खाने का बड़ा अवसर मिल गया है। इस चौतरफ़ा अफ़रा-तफ़री के माहौल में अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिये योगी ने तमाम सरकारी इमारतों को भगवा रंगने की मुहिम छेड़ दी है, यहां तक कि सरकारी बसें, औपचारिक परिधान और हज हाउस के दफ़्तर भी इसी रंग में रंग दिये गये।

कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर योगी हर लिहाज़ से ज़ीरो सिद्ध हो रहे हैं। वे कई बार घोषणा कर चुके हैं कि उनके राज में अपराधी या तो जेल जायेंगे या स्वर्ग। अन्यथा प्रदेश छोड़कर भाग जायें। लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा। पुरानी सरकार के आश्रय में पलने वाले अपराधी खामोश हुए तो नई पौध, जिसे नये शासकों का संरक्षण प्राप्त है, पैदा हो गयी। 'राहजनी' में जितने अपराधी लगे हुए हैं, उतने ही पुलिस वाले भी जुटे हुए हैं। एक को कानून का खौफ़ नहीं जबकि दूसरे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त! लगता है वह दिन भी दूर नहीं जब कानून-व्यवस्था सुधारने के नाम पर योगी की पुलिस खाकी वर्दी के बजाय भगवा वर्दी में दिखेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06